



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

जागृति

वर्ष: 65

अंक: 07

मुम्बई

जून 2022

बर्लिन में पीएम मोदी ने
'वोकल फॉर लोकल' और
खादी के लिए भारतीय
प्रवासियों का समर्थन मांगा



श्री नारायण राणे ने
एनआईएफटी, दिल्ली
में खादी उत्कृष्टता केंद्र
का उद्घाटन किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग



वर्ष: 65 अंक: 07 मुम्बई जून 2022

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष

श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक

एम. राजन बाबू

सह संपादक

संजीव पोसवाल

उप संपादक

सुबोध कुमार

डिजाईन व पृष्ठसजा

संजय सोमदे

वरिष्ठ कलाकार

चंद्रशेखर पुनवटकर
कलाकार

दिलिप पालकर
कलाकार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई -400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार

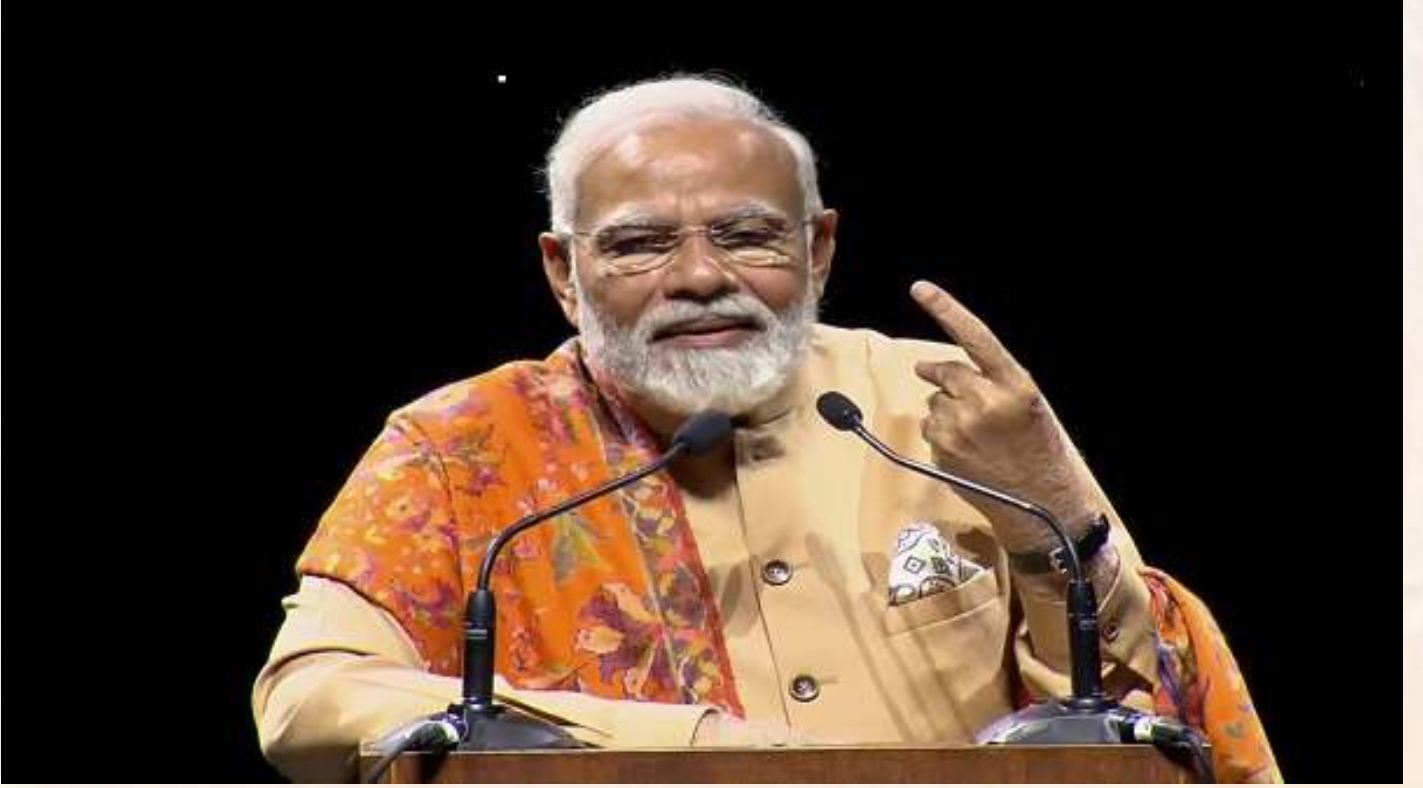
03-18

- ◆ बर्लिन में पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' और खादी के लिए भारतीय प्रवासियों का समर्थन मांगा **3**
- ◆ आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उप राज्यपाल बने **4**
- ◆ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की 107 कैंटीनों में खादी उत्पादों की बिक्री का शुभारम्भ किया **5**
- ◆ श्री नारायण राणे ने दिल्ली के एनआईएफटी में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया **6**
- ◆ तवांग में रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक खादी एरी रेशम प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र **8**
- ◆ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिये असम और अरुणाचल प्रदेश में काष्ठशिल्प और अगरबत्ती उद्योग को गति देने में केवाईआईसी का बड़ा प्रयास **10**
- ◆ केन्द्र सरकार ने बांस उद्योग के उच्च लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से "निर्यात प्रतिबंध" हटाया **12**
- ◆ खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया; भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ा **14**
- ◆ 13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग समयावधि के दौरान चालू योजना के अंतर्गत-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जारी रहेगा **15**
- ◆ आयोग ने मनाया विश्व मधुमक्खी दिवस अगर हम अपने जीवन को शहद की तरह मीठा बनाना चाहते हैं, तो मधुमक्खियों से एकजुट रहना सीखें **16**

मीडिया कवरेज

20 - 21

बर्लिन में पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' और खादी के लिए भारतीय प्रवासियों का समर्थन मांगा



बर्लिन, 03.05.2022: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के बर्लिन स्थित थियेटर एम पॉट्सडैमर प्लाट्ज़ में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। जर्मनी में जीवंत भारतीय समुदाय के 1600 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें भारत की पहल, "वोकल फॉर लोकल" में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खादी के विशेष उल्लेख के साथ यूरोप में भारतीय समुदाय को स्थानीय भारतीय उत्पादों के लिए वोकल बनने के लिए एक उत्साही अपील की, खादी ने मुख्य रूप से प्रधान मंत्री के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन से जिसने पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, श्री मोदी ने कहा कि 2021-22 में खादी का 1.15 लाख करोड़ रुपये का कारोबार एक ऐतिहासिक विकास है और उन्होंने देश या विदेश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को खादी को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। खादी, भारत की विरासत, परिवर्तन का एक उपकरण बनी हुई है।

म्यूनिख निवासी डॉ प्रवीण पाटिल ने कहा, "हम अपने जर्मन दोस्तों को खादी उपहार में देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जागरूकता के साथ-साथ मांग भी बढ़े।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे इन सभी वर्षों में जर्मनी में खादी की मांग कई गुना बढ़ गई है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने बर्लिन के पॉट्सडैमर प्लाट्ज़ के एक थिएटर में सभा को संबोधित करते हुए 'वोकल फॉर लोकल' और खादी के लिए समर्थन मांगा, जिसका भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

शेष पेज 4 पर..... ▶

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उप राज्यपाल बने

मई 23, 2022 : खादी को ब्रांड बनाने वाले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उप राज्यपाल (LG) नियुक्त किया गया। श्री सक्सेना कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आने वाले ऐसे पहले शख्स हैं जिन्हें LG बनाया गया है। अमूमन दिल्ली में उपराज्यपाल के पद पर रिटायर्ड IAS और IPS ही नियुक्त किए जाते रहे हैं। श्री सक्सेना 27 अक्टूबर 2015 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं।



विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा श्री विनय कुमार पायलट भी हैं।

खादी को दिलाई अलग पहचान

श्री विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल में खादी के कारोबार में 248% की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने केवल 7 सालों में 40 लाख नए रोजगार दिए। श्री सक्सेना के कार्यकाल के दौरान साल 2021-22 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 1.15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। उन्होंने खादी

को ब्रांड बनाने के लिए कई मार्केटिंग कैंपेन किए। रेमंड, अरविंद, एबीआरएफएल, निफ्ट, ग्लोबस आदि के साथ समझौता भी किया।



► पेज 3 से आगे.....

“मोदी एक बार फिर-2024” लंबे समय तक थिएटर में गूँजता रहा क्योंकि भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी के लिए अपना समर्थन दिखाया।

बर्लिन में भारतीय समुदाय के एक सदस्य हार्दिक देवड़ा ने कहा, “...प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर अभिभूत महसूस हुआ और हम अपने प्रधान मंत्री की वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को अपना समर्थन देकर खुश हैं।” उन्होंने कहा, “हम जर्मनी में अपने सहयोगियों के बीच इस बात का प्रचार करेंगे और अपने प्रधान मंत्री का हर संभव समर्थन करेंगे।”

समुदाय के एक अन्य सदस्य ने कहा कि “हालांकि वे एक विदेशी भूमि में रह रहे हैं, देशभक्ति बरकरार है और समुदाय हर संभव तरीके से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करता है।” बर्लिन में एक अन्य भारतीय ने कहा, मैं मोदी समर्थक होने पर गर्व महसूस करता हूँ, जो थिएटर में सभा में शामिल हुआ था।

पीएम मोदी ने कई देशों में प्रवासी कार्यक्रमों को संबोधित किया है और उन्होंने हमेशा विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारत की विकास यात्रा के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने की मांग की है।

“जर्मनी में, हम पीएम मोदी के पिछले भाषणों को सुन रहे हैं जिसमें वह कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। अब, उसे लाइव सुनना एक सपने के सच होने जैसा है, ”जर्मनी में रहने वाले एक अन्य भारतीय ने कहा।

पीएम मोदी के भाषण को तीन देशों की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के एक हिस्से के रूप में जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिलीं।

भारतीय प्रधान मंत्री 02 मई, 2022 को जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ट्स के साथ छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) में भाग लिया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।



केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की 107 कैंटीनों में खादी उत्पादों की बिक्री का शुभारम्भ किया

09 मई, 2022, नई दिल्ली : केंद्र सरकार का "स्वदेशी" अभियान अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार के लिए अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में हाथ से बने खादी उत्पादों की बिक्री शुरू कर रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 मई, 2022 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 107 कैंटीनों में खादी उत्पादों की बिक्री की शुरुआत की। गृह मंत्री ने कहा कि देश में अर्धसैनिक बलों की सभी कैंटीन में जल्द ही खादी उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा, "गांधी जी के लिए खादी स्वदेशी का प्रतीक थी और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने का एक साधन भी है। खादी ही शुद्धता की गारंटी देती है। मुझे खुशी है कि अर्धसैनिक बलों की 107 कैंटीनों में खादी उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है और जल्द ही देश भर में अर्धसैनिक बलों की सभी कैंटीनों में खादी उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा।" गृह मंत्री ने असम के तामूलपुर में सीमा सुरक्षा बल-बीएसएफ की केंद्रीय कार्यशाला और स्टोर के शिलान्यास समारोह के अवसर पर खादी उत्पादों की बिक्री के शुभारंभ के दौरान ये बात कही।

इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व सरमा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और सीमा सुरक्षा बल-बीएसएफ तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल-सीआरपीएफ के महानिदेशक उपस्थित थे।

श्री शाह ने देश में स्थायी ग्रामीण रोजगार सृजित करने के लिए केवीआईसी की प्रशंसा की। गृह मंत्री ने कहा कि

केवीआईसी की प्रमुख योजनाओं जैसे हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, चमड़ा और बढ़ई सशक्तिकरण योजनाओं में असम के बोडोलैंड में स्थायी रोजगार सृजित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, "यदि केवीआईसी लोगों को अपनी स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ना शुरू कर देता है, तो यह निश्चित रूप से बोडोलैंड में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर देगा और राष्ट्र के विकास के साथ हथियार डालने वाले बोडो युवाओं को भी फिर से राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ देगा।"

गृह मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, केवीआईसी ने वर्ष 2021-22 में 1.15 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार करते हुए लगभग 250 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई।

गृह मंत्री ने इससे पहले, स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए, सभी सीएपीएफ कैंटीनों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से अधिकतम "स्वदेशी" उत्पाद बेचना अनिवार्य कर दिया था। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज, सूती तौलिए, शहद, कच्ची घानी सरसों का तेल, अगरबत्ती, दलिया, पापड़, अचार और आंवला उत्पाद आदि सहित 32 उत्पादों की आपूर्ति दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में स्थित कैंटीनों में की जाएगी।

सरसों के तेल, सूती दरी और ऊनी कंबल की आपूर्ति के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ केवीआईसी के ऐतिहासिक समझौतों के बाद यह संभव हो सका है। अब तक केवीआईसी ने विभिन्न अर्धसैनिक बलों को लगभग 17 करोड़ रुपये के उत्पादों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। आपूर्ति में 5.50 करोड़ रुपये की कच्ची घानी सरसों का 3 लाख किलोग्राम (3000 मीट्रिक टन) तेल, 11 करोड़ रुपये मूल्य के 2.10 लाख बिछाने की सूती दरियां

शेष पेज 14 पर.....▶

श्री नारायण राणे ने दिल्ली के एनआईएफटी में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया

09 मई, 2022, नई दिल्ली : खादी को अपने फैब्रिक्स तथा क्लॉदिंग लाइन में विविधता लाने के द्वारा प्रचलित करने तथा गुणवत्ता मानकों को उन्नत बनाने के लिए खादी संस्थानों में कौशल निर्माण करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ मिलकर कार्य किया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में सीओईके हब और गांधीनगर, शिलांग, कोलकाता और बेंगलुरु में इसकी शाखाओं का उद्घाटन नई दिल्ली के एनआईएफटी परिसर में किया।

श्री राणे ने सीओईके वेबसाइट भी लॉन्च की जहां खादी

संस्थानों के उपयोग के लिए नवीनतम डिजाइन और प्रौद्योगिकी युक्तियां अपलोड की जाएंगी।

इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि खादी पर देश के विकास में योगदान देने और "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी के साथ-साथ डिजाइनरों का उत्तरदायित्व है कि वे खादी में नए डिजाइन पेश करें और इसे युवा के लिए आकर्षक बनाएं। उन्होंने कहा, "भारतीय फैशन उद्योग में अन्य प्रमुख कंपनियों की तुलना में खादी की लोकप्रियता का आकलन करने की आवश्यकता है। हमारे डिजाइनरों को निश्चित रूप से खादी में इस तरह के आकर्षक डिजाइन प्रस्तुत करने चाहिए कि लोग खादी खरीदने के लिए उतने ही आकर्षित हों जितना कि

शेष पेज 7 पर.....▶



► पेज 6 से आगे

वे दूसरे कपड़ों की खरीद के लिए आकर्षित होते हैं।”

इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश, एमएसएमई सचिव श्री बी.बी. स्वैन और सचिव कपड़ा श्री यू.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

किया जाएगा। सीओईके घरेलू और वैश्विक खरीदारों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए फैब्रिक्स और क्लॉदिंग बनाने के लिए नवीनतम डिजाइन प्रस्तुत करने और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए काम करेगा। सीओईके खादी की प्रोडक्ट लाइन में विविधता लाने के लिए निर्माण प्रक्रिया में नए डिजाइन और तकनीक प्रस्तुत करने के लिए खादी संस्थानों में भी



इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश, एमएसएमई सचिव श्री बी.बी. स्वैन और सचिव कपड़ा श्री यू.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने सीओईके की स्थापना के लिए केवीआईसी और एनआईएफटी की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह खादी को फैशनबल और वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सीओईके की स्थापना के लिए पिछले साल केवीआईसी और एनआईएफटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस परियोजना को 3 साल की अवधि में लागू

कौशल निर्माण करेगा।

इसके अतिरिक्त, सीओईके नए खादी उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और प्रचार, विजुअल मर्चेन्डाइजिंग और पैकेजिंग में भी योगदान देगा और भारत तथा विदेशों में खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों का आयोजन करके खादी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाएगा।



► पेज 7 से आगे

एनआईएफटी द्वारा खादी फैब्रिक और क्लॉदिंग पर तैयार नए समकालीन डिजाइन सीओईके की प्राथमिक सहायता से खादी संस्थानों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए सीओईके और केवीआईसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। सीओईके द्वारा खादी के लिए एक नॉलेज पोर्टल भी विकसित किया

जाएगा।

एनआईएफटी ने पेशेवरों को नियुक्त किया है, और आरंभ में, एनआईएफटी टीम द्वारा 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खादी संस्थानों पर एक नैदानिक अध्ययन किया गया है। खादी फैब्रिक/उत्पादों के नए समकालीन डिजाइनों के चालू वित्त वर्ष में लॉन्च होने की उम्मीद है।



तवांग में रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक खादी एरी रेशम प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र

12 मई, 2022, नई दिल्ली : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने और टिकाऊ रूप से स्थानीय रोजगार सृजन के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केवीआईसी ने चीन और भूटान की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक और "खादी एरी रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र" स्थापित किया है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में बसे रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस केंद्र की स्थापना बौद्ध संस्कृति संरक्षण समिति, बोमडिला की सहायता से की गई है। समिति ने सिल्क सेंटर के लिए भवन उपलब्ध कराया है। दूसरी ओर केवीआईसी ने हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और वारपिंग ड्रम आदि जैसे

आवश्यक बुनियादी ढांचे प्रदान किए हैं। केंद्र तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों की 20 महिला कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में खादी रेशम केंद्र की स्थापना भारत के दूर-दराज के स्थानों में सतत विकास करने और "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत स्थानीय लोगों के लिए आजीविका सृजन के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है। यह अरुणाचल प्रदेश में केवीआईसी द्वारा 2 वर्ष से कम समय में स्थापित किया गया दूसरा रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है। इससे पहले, केवीआईसी ने 17 सितंबर, 2020 को अरुणाचल प्रदेश के गांव चुल्लु में एरी सिल्क प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया था। केवीआईसी ने दिसंबर 2020 में तवांग में 1000 वर्ष पुरानी विरासत मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग को भी पुनर्जीवित किया था, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" में भी की थी।





केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि "खादी एरी रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र" का उद्देश्य पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करना है, जो पिछले कुछ दशकों में लगभग नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि तवांग में यह सुविधा पूरे क्षेत्र में कटाई और बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगी। कारीगरों को प्रशिक्षण और एरी सिल्क के उत्पादन को समर्थन देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और क्षेत्र का सतत विकास होगा।

एरी सिल्क पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वदेशी है। निफ्ट के युवा डिजाइनर और पेशेवर खादी कारीगरों को इस केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि जनजातीय युवाओं की आधुनिक रुचि के अनुरूप नए डिजाइन प्रस्तुत किए जा सकें और ट्रेंड के अनुसार पहनने के कपड़े तैयार किए जा सकें।

रेशम सदियों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन इन बाजारों में कम गुणवत्ता वाले रेशम की भरमार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेशम उद्योग को भी नष्ट कर दिया। यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय आबादी, समान रूप से पुरुष और महिलाएं, एरी सिल्क और खादी सूती कपड़े पहनती है, जो उनके समतावादी जनजातीय समाज के लिए काफी महत्व रखता है।

केवीआईसी का उद्देश्य तवांग आने वाले पर्यटकों के साथ केंद्र को जोड़ना और इस तरह स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए एक निश्चित बाजार प्रदान करना है। उत्पादन केंद्र बाजार की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर होगा।



स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिये असम और अरुणाचल प्रदेश में काष्ठशिल्प और अगरबत्ती उद्योग को गति देने में केवीआईसी का बड़ा प्रयास

16 मई, 2022, नई दिल्ली : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)ने असम और अरुणाचल प्रदेश में 100 महिलाओं सहित 150 प्रशिक्षित खादी शिल्पकारों को स्व-रोजगार की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने

अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तवांग के स्थानीय जनजातीय युवाओं के लिये स्थायी रोजगार उत्पन्न हो सकें। इसका एक और उद्देश्य है राज्य की पारंपरिक काष्ठकला को दोबारा जीवित करना। सभी काष्ठ शिल्पकार बीपील परिवारों से सम्बंधित हैं तथा केवीआईसी 20



अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 50 शिल्पकारों को काष्ठकला की मशीनें वितरित कीं। इसी तरह उन्होंने गुवाहाटी, असम में शिल्पकारों को अगरबत्ती बनाने वाली 50 मशीनें और अचार बनाने वाली 50 मशीनों का वितरण किया।

पहली बार केवीआईसी ने मशीनों द्वारा काष्ठकला का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम

दिनों का समग्र प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद इन शिल्पकारों को मशीनें प्रदान की जाती हैं।

श्री सक्सेना ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएम-ईजीपी) के तहत 50 महिला शिल्पकारों को अगरबत्ती बनाने वाली 50 मशीनें वितरित कीं, ताकि वे अपनी अगरबत्ती निर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें। इसका एक और उद्देश्य है कि स्थानीय

अगरबत्ती उद्योग को मजबूत किया जाये। उल्लेखनीय है कि असम में अगरबत्ती निर्माण में बहुत रोजगार हैं। केवीआईसी ने इसके लिये एक व्यापारिक साझेदार को भी जोड़ा है, जो असम का सफल स्थानीय अगरबत्ती निर्माता है। वह कच्चा माल उपलब्ध करायेगा तथा इन 50 महिला उद्यमियों को मजदूरी चुकाते हुये उनके द्वारा बनाई गई समस्त अगरबत्तियां खरीदेगा।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि पूर्वोत्तर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुये खादी गतिविधियों को प्रधानमंत्री की परिकल्पना “आत्मनिर्भर भारत” के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, “केवीआईसी ने पूर्वोत्तर में स्थायी रोजगार सृजन और पारंपरिक शिल्प को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया है। केवीआईसी के समर्थन से काष्ठशिल्प, अगरबत्ती निर्माण और अचार बनाने जैसे कृषि व खाद्य-आधारित उद्योगों के बल पर स्थानीय युवा व महिलायें सशक्त बनेंगी तथा उनके घर में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।”



उल्लेखनीय है कि हाल में ही केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में दो 'एरी रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र' खोले हैं। साथ ही तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग को दोबारा जीवित किया गया है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी ने पिछले दो वर्षों में अगरबत्ती और गोल बांस की छड़ी निर्माण सहित बांस उत्पादों की 430 इकाइयां असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की हैं।



केन्द्र सरकार ने बांस उद्योग के उच्च लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से “निर्यात प्रतिबंध” हटाया



20 मई, 2022, नई दिल्ली :केन्द्र सरकार ने बांस के चारकोल पर से “निर्यात प्रतिबंध” हटा लिया है। यह एक ऐसा कदम है जो कच्चे बांस के अधिकतम उपयोग और भारतीय बांस उद्योग को उच्च लाभ की सुविधा प्रदान करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जो देश में हजारों बांस आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है, लगातार सरकार से बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने का अनुरोध कर रहा था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के

व्यापक लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की थी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “वैध स्रोतों से प्राप्त बांस से बने सभी बांस के चारकोल के निर्यात को अनुमति इस आशय के स्रोत संबंधी उपयुक्त उचित दस्तावेज / मूल प्रमाण पत्र, जो यह प्रमाणित करे कि चारकोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया बांस वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है, के आधार पर दी जाती है।”

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने इस नीतिगत संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस निर्णय से कच्चे

बांस की उच्च लागत में कमी आएगी और बांस आधारित उद्योग, जोकि ज्यादातर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, को आर्थिक रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांस के चारकोल की भारी मांग है और सरकार द्वारा निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने से भारतीय बांस उद्योग इस अवसर का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर भारी मांग का फायदा उठाने में सक्षम होगा। यह बांस के कचरे का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार प्रधानमंत्री के कचरे से धन की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा।”

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय बांस उद्योग वर्तमान में बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च लागत की समस्या से जूझ रहा है। भारत में, बांस का उपयोग ज्यादातर अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है। अगरबत्ती के निर्माण के क्रम में अधिकतम 16 प्रतिशत बांस का उपयोग बांस की छड़ें बनाने के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है।

नतीजतन, गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस की लागत 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के दायरे में है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

हालांकि, बांस के चारकोल का निर्यात बांस के कचरे का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के कारोबार को और अधिक लाभदायक बनाएगा। मांस भूनने की सीक (बारबेक्यू), मिट्टी के पोषण और सक्रियकृत चारकोल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में बांस के चारकोल की संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी संभावनाएं हैं।

इससे पहले बांस आधारित उद्योगों, विशेष रूप से अगरबत्ती उद्योग, में अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 2019 में केन्द्र सरकार से कच्चे अगरबत्ती के आयात के संबंध में नीतिगत बदलाव लाने और वियतनाम तथा चीन से भारी मात्रा में आयात किए जाने वाले गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क लगाने का अनुरोध किया था।

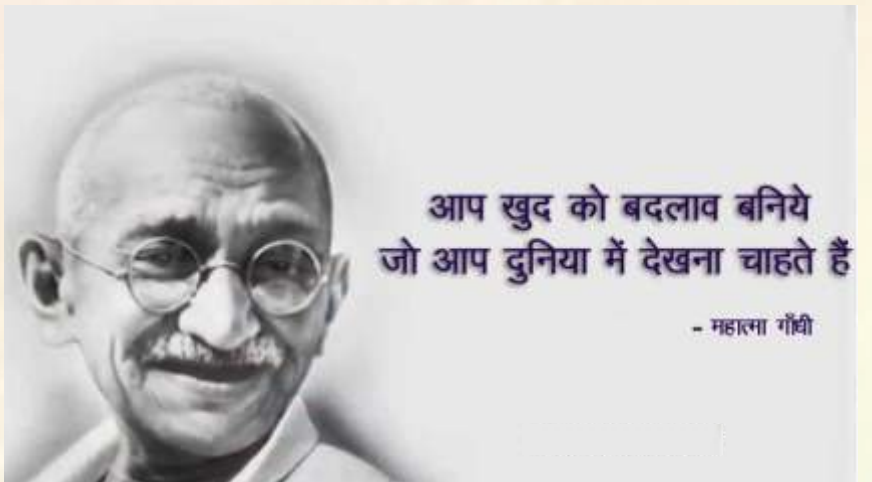
इसके बाद सितंबर 2019 में वाणिज्य मंत्रालय ने कच्ची अगरबत्ती के आयात पर "प्रतिबंध" लगा दिया था और जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था।



► पेज 5 से आगे

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों और 40 लाख रुपये के ऊनी कंबल शामिल हैं।

अर्धसैनिक बलों की कैटीन विशेष रूप से खादी उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगी और इसका सीधा असर केवीआईसी के उत्पादन तथा बिक्री पर पड़ेगा। अर्धसैनिक बलों को खादी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है जिसमें खादी कपड़े और रेडीमेड वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन तथा खाने-पीने की वस्तुएं और हर्बल उत्पाद शामिल होंगे।



खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया; भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ा

30 अप्रैल, 2022, नई दिल्ली : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने एक उच्चतम महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जो भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियों के लिए अभी एक दूरस्थ लक्ष्य बना हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन को धन्यवाद देते हुए केवीआईसी ने पहली बार 1.15 लाख करोड़ रुपये का जबरदस्त कारोबार किया है, जो देश में किसी भी एफएमसीजी कंपनी द्वारा अभूतपूर्व है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली केवीआईसी देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, केवीआईसी का कुल कारोबार पिछले वर्ष यानी 2020-21 में 95,741.74 करोड़ रुपये की तुलना में 1,15,415.22 करोड़ रुपये रहा।

इस प्रकार केवीआईसी ने वर्ष 2020-21 से 20.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और वर्ष 2014-15 की तुलना में 2021-22 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 172 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान सकल बिक्री में 248 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

केवीआईसी ने इस व्यापक कारोबार लक्ष्य को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पहले 3 महीनों में यानी 2021 में अप्रैल से जून तक देश में आंशिक लॉकडाउन के बावजूद हासिल किया है।

पिछले एक वर्ष के प्रदर्शन को देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि खादी क्षेत्र पर देखी जा सकती है, जिसने 2020-21 में 3528 करोड़ रुपये से 43.20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और 2021-22 में यह 5052 करोड़ रुपये हो गया है।

पिछले 8 वर्षों में, यानी 2014-15 से 2021-22 में खादी क्षेत्र में उत्पादन में 191 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि खादी की बिक्री में 332 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, अकेले ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारोबार 2021-22 में 1,10,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 92,214 करोड़ रुपये था। पिछले 8 वर्षों में, 2021-22 में ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में 172 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री में 245 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी के अभूतपूर्व विकास का श्रेय देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन को दिया। साथ ही, नवीन योजनाओं, रचनात्मक विपणन विचारों और विभिन्न मंत्रालयों के सक्रिय समर्थन ने भी हाल के वर्षों में खादी के विकास में इजाफा किया है।

"स्वदेशी" और विशेष रूप से "खादी" को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की बार-बार अपील ने चमत्कार किया है। आज खादी देश की सभी एफएमसीजी कंपनियों से बहुत आगे है। नए वैज्ञानिक तरीकों को नियोजित करके और खादी की उत्पाद श्रृंखला में विविधता लाने से केवीआईसी ने इतनी बड़ी वृद्धि हासिल करने में सफल रही है, जिसकी बराबरी कोई अन्य एफएमसीजी कंपनी नहीं कर सकती।

विशेष रूप से, लोगों ने "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" के प्रधानमंत्री के आह्वान की उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। पिछले कुछ वर्षों में, केवीआईसी का मुख्य ध्यान कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने पर रहा है।

शेष पेज 18 पर.....▶

13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग समयावधि के दौरान चालू योजना के अंतर्गत जारी रहेगा- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

30 मई, 2022, नई दिल्ली : भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम -एमएसएमई मंत्रालय, गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) लागू कर रही है। इस के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग-केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर पर केवीआईसी के राज्य कार्यालय, राज्य केवीआईबी और डीआईसी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। कॉयर बोर्ड कॉयर इकाइयों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

बैंकों द्वारा निधियों की स्वीकृति और जारी करने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया <https://www.kviconline.gov.in/pmeeportal/pmegphome/index.jsp> पोर्टल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है।

वर्ष 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से, लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 64 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित स्थायी रूप से रोजगार पैदा करने में सहायता मिली है। सहायता प्राप्त लगभग 80 प्रतिशत इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50 प्रतिशत इकाइयाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणियों के स्वामित्व में हैं।

पीएमईजीपी को अब 13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। मौजूदा योजना में निम्नलिखित प्रमुख

संशोधन/सुधार किए गए हैं:

- अधिकतम परियोजना लागत को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर विनिर्माण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपये और सेवा इकाइयों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- पीएमईजीपी के लिए ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा संशोधित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र के रूप में शामिल माना जाएगा।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को ग्रामीण या शहरी श्रेणी के बावजूद सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति दी गई है।
- आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर श्रेणी के अंतर्गत पीएमईजीपी आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों के रूप में माना जाएगा और वे उच्च सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

प्रमुख प्रभाव: योजना पांच वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

शामिल किए गए राज्य/जिले: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

मार्जिन मनी सब्सिडी की उच्च दर - शहरी क्षेत्र में परियोजना

शेष पेज 18 पर.....▶

आयोग ने मनाया विश्व मधुमक्खी दिवस

अगर हम अपने जीवन को शहद की तरह मीठा बनाना चाहते हैं, तो मधुमक्खियों से एकजुट रहना सीखें

मधुमक्खी पालन एक व्यापक और वैश्विक गतिविधि है, जिसमें लाखों मधुमक्खी पालक अपनी आजीविका और कल्याण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियां - जंगली परागणकों के साथ, जैव विविधता को बनाए रखने, कई पौधों के अस्तित्व और प्रजनन को सुनिश्चित करने, वन पुनर्जनन का समर्थन करने, जलवायु परिवर्तन के लिए स्थिरता और अनुकूलन को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

20 मई, 2022 ने केवीआईसी अपने केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शहद मिशन कार्यक्रम के तहत विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्यालय केवीआईसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने मधुमक्खी पालकों और केवीआईसी के अधिकारियों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने प्रेरणादायक संदेश में "विश्व मधुमक्खी दिवस" के अवसर

पर मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी मधुमक्खी पालकों को बधाई देते हुए दोहराया कि "हनी मिशन" 2017 में शुरू किया गया था और इन 4 वर्षों में, वास्तव में उत्साहजनक परिणाम रहे हैं।

उन्होंने बताया, केवीआईसी ने अब तक देश के कोने-कोने में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं को 1.70 लाख से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की है। साथ ही केवीआईसी ने प्रकृति में 8000 मिलियन से अधिक मधुमक्खियों को जोड़ा है, जो अपने



आप में एक रिकॉर्ड है।

उन्होंने लोगों से मानव जाति के बड़े लाभों के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन को शहद की तरह मीठा बनाना चाहते हैं, तो हमें मधुमक्खियों से एकजुट रहना सीखना होगा, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारा देश हो या हमारा अपना जीवन हो।



केवीआईसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केवीआईसी हमेशा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों में सबसे आगे रहा है और केवीआईसी ने वर्ष 2017 से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। केवीआईसी ने हनी मिशन कार्यक्रम को बढ़ावा देकर और इसे

रोजगार के अवसरों में बदलकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया।

केवीआईसी की मुख्य सतर्कता अधिकारी सुश्री संघमित्रा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण शुक्ल ने कार्यक्रम में संबोधन किया, कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी के सभी कार्यक्रम निदेशक एवं अधिकारी उपस्थित थे।



► पेज 15 से आगे

खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार.....

आर्थिक संकट का सामना करते हुए, बड़ी संख्या में युवाओं ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को अपनाया जिससे ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने प्रमुख स्टोर पर खादी की एकल-दिन की बिक्री भी 30 अक्टूबर 2021 को 1.29 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।



► पेज 16 से आगे

13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक.....

लागत का 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी और विशेष श्रेणी के आवेदकों और सीमावर्ती जिले के आवेदकों के लिए में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

संशोधित योजना के दिशानिर्देश वेबसाइट: msme.gov.in पर उपलब्ध होंगे।





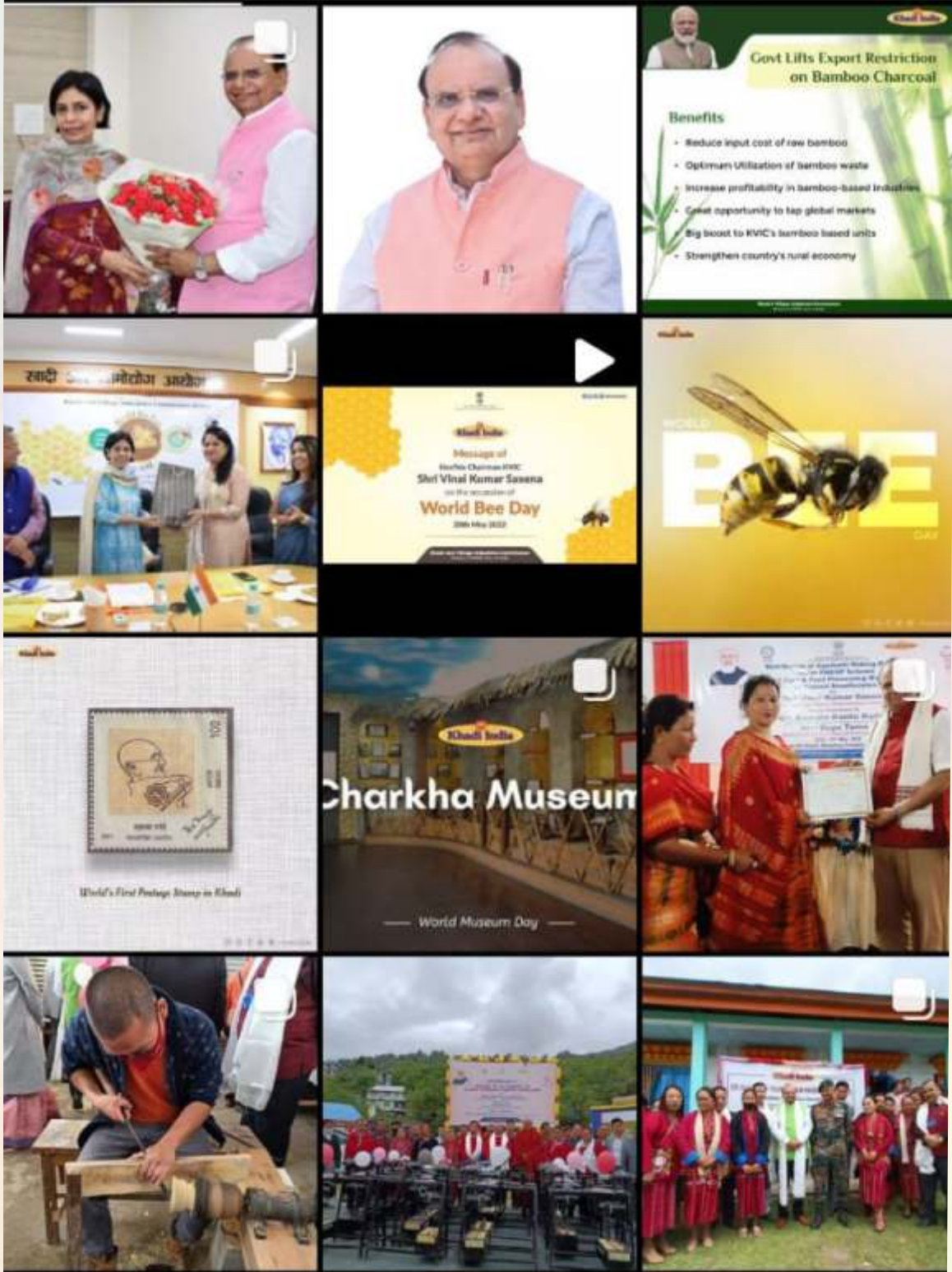
ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 50 नग गाजीपुर जिले के मोची को 31.03.2022 को क्रेश कोर्स प्रशिक्षण दिया गया और केवीआईसी, वाराणसी द्वारा फुटवियर रिपेयरिंग टूल किट बॉक्स वितरित किया गया।



आयोग के मंडलीय कार्यालय, वाराणसी ने जीएम, बीएलडब्ल्यू, वाराणसी के अनुरोध पर बनारस रेलवे कारखाना (बीएलडब्ल्यू) वाराणसी के परिसर में अन्य खादी उत्पादों के साथ 10 दिनों (01.06.2022 से 10.06.2022) राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। उक्त प्रदर्शनी का उद्घाटन 01.06.2022 को जीएमबीएलडब्ल्यू और निदेशक, केवीआईसी, वाराणसी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन केवीआईसी की वित्तीय सहायता के बिना किया जा रहा है।

केवीआईसी सोशल मीडिया पर

फेसबुक व इंस्टाग्राम पोस्ट



केवीआईसी सोशल मीडिया पर

फेसबुक व इंस्टाग्राम पोस्ट





सत्यमेव जयते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India.

Khadi India

हस्तनिर्मित

स्विटजरलैंड से पेन और घड़ियाँ,
फ्रांस से चमड़े के जूते,
इटली से पर्स व बटुए और
मिश्र से कॉटन वस्त्र.

आप इन विदेशी वस्तुओं के लिए हजारों खर्च करते हैं और खरीदते हैं,
और जब भारतीय हस्तशिल्प खरीदने की बात आती है, आप संकोच करते हैं !

इस अवसर पर

अपने शहर के किसी खादी इण्डिया आउटलेट पर जाएं,
गर्व से खरीदें उच्च गुणवत्ता के हस्तनिर्मित वस्त्र और उत्पाद,
जो आपके देशवासियों द्वारा ग्रामीण भारत में बनाये गए हैं !

क्यों

विदेशी हाथों को भुगतान करें ?
भारत की आत्मीयता को महसूस करें



खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट : www.kvic.org.in



KVIC ARTWING 2018